

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
Notification

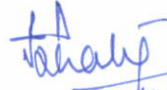
New Delhi, the 03<sup>rd</sup> November, 2017

S.O..... (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Judicature at Madras, hereby designates the following Courts mentioned in column (1) the Table below as Special Court for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the said sub-section, namely:-

Table

Courts (1)	Jurisdiction as Special Court (2)
XV Additional Court, XVI Additional Court of City Civil Court, Chennai	State of Tamil Nadu except Districts of Coimbatore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Krishnagiri, Namakkal, Nilgiris, Salem and Tiruppur.

[F.No. 01/12/2009-CL-I (Vol.IV)]

  
13/11/2017  
AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना


नई दिल्ली, तारीख 03 नवंबर, 2017

का.आ. \_\_\_\_\_ (अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ (1) में उल्लिखित निम्नलिखित न्यायालयों को, उक्त उपधारा के अधीन दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों का शीघ्र विचारण करने के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है, अर्थात् -

सारणी

न्यायालय (1)	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता (2)
नगर सिविल न्यायालय, चैन्नई का XV अपर न्यायालय, XVI अपर न्यायालय	कोयम्बटूर, धर्मापुरी, डिंडीगुल, इरोड, कृष्णागिरी, नामक्कल, नीलगिरी, सेलम और तिरुपुर को छोड़कर तमिलनाडु राज्य

[फाइल संख्या 1/12/2009-सीएल-I-(भाग.IV)]

  
03/11/2017  
(अमरदीप सिंह भाटिया)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार